

प्रेषक

अरविन्द सिंह ह्यांकी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 02 जुलाई, 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत देहरादून-पौंटा मोटर मार्ग (किमी0 34.500 से 40.200 तक) का बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय तथा निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये देहरादून-पौंटा मोटर मार्ग (किमी0 34.500 से 40.200 तक) का बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढीकरण कार्य लागत रु. 150.00 लाख, की टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रु0 147.70 लाख की लागत के सम्बन्ध में तथा बारहवें वित्त आयोग के प्राविधानों के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रसंगत कार्य हेतु 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 32456.00 लाख संस्तुत अनुदान के सापेक्ष शासनादेश संख्या 604/11(3)/06-01(सा0)/06, दिनांक 12.09.2006 द्वारा रु. 25229.69 लाख शासनादेश संख्या 13/11(3)/09-01(सा0)/06, दिनांक 02.03.2009 द्वारा स्वीकृत रु. 7078.79 लाख कुल रु. 32308.48 लाख की स्वीकृति के पश्चात् अवशेष धनराशि की शासनादेश संख्या-277/11(3)/09-01(सा0)/06 टी.सी.व. दिनांक 04.06.2009 के द्वारा आपके निर्वर्तन पर रखी गयी रु. 4057.00 लाख (रुपये चालीस करोड़ सत्तावन लाख मात्र) की धनराशि में से रु. 147.52 लाख (रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- 1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- 2- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी लोक निर्माण विभाग से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। क्योंकि उक्त कार्य बारहवें वित्त से सम्बन्धित है। सक्षम प्राधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि प्राविधिक स्वीकृति देते समय सारणी 10.7 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।
- 3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय क्योंकि इस स्वीकृति में धन एवं समय में बढोतरी संभव नहीं होगी।
- 4- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8/7/09

- 6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 7- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जानी सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- 9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर उस पर कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 10- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 11- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।
- 12- अनुरक्षण का कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली, 2008 तथा उक्त के क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन में कराया जायेगा।
- 13- अनुरक्षण कार्य दिनांक 31.12.2009 तक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 10.01.2010 तक उपलब्ध करा दिये जाय, ताकि भारत सरकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया जा सकें।
- 14- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 15- स्वीकृत कार्यों पर व्यय 12 वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 16- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या: 173/XXVII(2)/2009 दिनांक 01 जुलाई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अरविन्द सिंह हयांकी)  
अपर सचिव।

पृ.सं. 343 (1)/11(3)09 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल, पौड़ी।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग 1 व 2, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से  
11/6/09  
(महिमा)  
अनु सचिव।